region and Tripura is very weak. In fact, we had requested the Government that a railway line linking Agartala and Kumarghat should be provided. But that demand was also not accepted by the Government and there is no mention of it in the Railway Budget. This is creating a lot of hardships to the people of Tripura. In an otherwise volatile and politically unstable situation that is prevailing in the North-East, Tripura is the only state where there is a stable and popular Government. Sir, the Central Government Should immediately restore the flights as they were earlier.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal); Sir, I fully associate myself with it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Shankar Dayal Singh. Not present. Shri Maheshwar Singh.

Need to Reduce Air Fare

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से नागरिक उड्डयन एंव पर्यटन मंत्री जी का ध्यान एक विशेष महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, यह बात सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों पर्यटक स्थल हैं जहां न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक आते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय तीन हवाई पट्टियां हैं एक कुल्लू में, एक शिमला में और एक कांगड़ा में। गत वर्ष तक इन हवाई पट्टियों पर वायुदूत सेवा उपलब्ध थी और उस समय भी वहां का किराया देश के बाकी भागों के मुकाबले में सर्वाधिक था। उदाहरण के लिये दिल्ली से कुल्लू की उड़ान सवा घंटे की है लेकिन किराया 1767 रूपया था। मैंने उस समय भी यह मामला इस माननीय सदन में उठाया था।

उपसभाध्यक्ष: (श्री सतीश अग्रवाल): कुल कितना किलोमीटर है।

श्री महेश्वर सिंह: कुल सवा घंटे की उड़ान है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): किलोमीटर कितना है, वाई रोड?

श्री महेश्वर सिंह: यह तो एक्जेक्टली मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सवा घंटे की फ्लाइट है और 1767 रुपया किराया था। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वे इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। लेकिन जैसे ही वायुदूत की सेवायें बंद कर दी गयी और हमें प्राइवेट एयर टैक्सी के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया तो उन्होंने तुरंत वह किराया बढ़ाकर 2067 रुपया कर दिया। मैंने फिर इस माननीय सदन में यह मामला उठाया और मंत्री महोदय ने कहा कि एयर कारपोरेशन ऐक्ट पारित होने के बाद ही उनको यह अधिकार मिलेगा और उसके बाद ही किराया निर्धारित करने में वे हस्तेक्षप कर सकेंगे। लेकिन यह खेद का विषय है कि एयर कारपोरेशन ऐक्ट पास हो गया और उसके बाद कुल्लू का किराया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2550 रूपया एक तरफा लिया जा रहा है और मंत्री महोदय चुप्पी साधे बैठे हैं। अनेकों बार यह मामला मैं उनके ध्यान में ला चुका हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी इस फ्लाइट में जगह नहीं मिलती है। इसका कारण है हनीमून कपल। अगर हनीमून कपल न हों तो यह फ्लाइट बिल्कुल बंद हो जाय। आप इस बात से सहमत होंगे कि जो हनीमून कपल जाते हैं उनको जिंदगी मे एक बार जाना होता है और यह पैसा उनको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है, उनको उपहार में यह पैसा मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसमें हस्तक्षेप करें और जो अर्चना एयर वेज है, उसका नाम अर्चना एयरवेज नहीं बल्कि हनीमून कपल एयरवेज रखा जाये क्योंकि अगर ये हनीमून कपल न मिलें तो कुल्लू की फ्लाइट ठप्प हो जाये। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस लूट से पर्यटकों और उपभोक्ताओं को बचायें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): What better place can there be on earth than kulu? Anyway I wish to inform the hon. Members...(*Interruptions*)...

SHRI CHATURANAN MISHRA (BIHAR): Sir, I fully associate myself with what Shri Singh has said.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, I totally agree with Mr. Singh that this is going on because

the Vayudoot's services are not available The private operators are squeezing money from the people of Himachal Pradesh. Same is the case with Simla. The fare is being hiked like anything

श्री महेश्वर सिंह: शिमला का 2 हजार है। अगर वाया शिमला जाना पडे तो 35 सौ रूपया लिया जा रहा है।

SHRI JAGESH DESAI: I think that something should be done immediately. The private opearators cannot be given a licence to charge the fare as they like I think the Minister should look into this and see that private operators don't charge high fares...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Hon. Members. I want to know the sense of the House There are five Members more so far as the Special Mentions are concerned I would like to know whether you want to finish the Special Mentions and adjourn the House then so that after one full hour lunch, we can start the legislative business.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Let us finish the Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN: Okay Now, Mr. Miri

Demand for Establishment of Tenth Zonal Railway in Bilaspur, Madhya Pradesh

श्री गोविन्दराम मीरी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के बिलासपुर को रेलवे का दसवां जोन बनाने के बाबत माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, दक्षिण पूर्व रेलवे में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला करीब 60 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के कोरवा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग भिलाई रेलवे हैं, जो कि बिलासपुर संभाग में है। बिलासपुर की जनता द्वारा गत कई वर्षों से बिलासपुर में रेलवे जोन खोलने की मांग की जा रही है। लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हो रही है और उसका मुख्यालय बिलासपुर से 720 किलोमीटर दूर कलकत्ता में है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कुल 119 रेलवे स्टेशन हैं और करीब 1,000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन,है, जब कि देश में रेलवे स्टेशन 7,065 तथा रेलवे लाइन 61,385 किलोमीटर लम्बी है।

महोदय, दक्षिण पूर्व रेलवे का बिलासपुर डिवीजन भारतीय रेलवे के सभी 58 डिवीजन मे सर्वाधिक आय देने वाला एवं लोडिंग करने वाला डिवीजन है, इतना ही नही 9 जोनल रेलवे में से 7 जोनल रेलवे से भी अधिक डिवीजन होने के बावजूद आय दे रहा है। बिलासपुर डिवीजन मे बिछाई गयी। 1127 रूट किलोमीटर रेलवे लाईन प्रति किलोमीटर 76 लाख रूपये आय देती है जब कि भारतीय रेलवे की औसत आय प्रति किलोमीटर 13 लाख रूपये की है। भारतीय रेलवे के मुनाफे में बिलासपुर डिवीजन का हिस्सा 20 प्रतिशत, 732 करोड़ के मुनाफे में 156 करोड़ का है, जब कि डिवीजनों की संख्या एवं किलोमीटर की लंबाई के आधार पर उसका हिस्सा 2 प्रतिशत होना था।

किन्तु उपरोक्त योगदान के बावजूद भारतीय रेलवे, बिलासपुर डिवीज़न को बदले में क्या दे रही है? ज़रा इस पर भी गौर करें। बिलासपुर डिवीज़न में एक भी रेल लोकोमोटिवह, डीज़ल, इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना या कोच फेक्टरी या वैगन निर्माण या व्हील एंड एक्सल प्लांट नहीं है। बिलासपुर डिवीज़न में "कंट्रोलर आफ स्टोर्स एंड परचेस" का कार्यालय नहीं होने से यहां से भारतीय रेलवे द्वारा कोई खरीदी नहीं की जाती है। बिलासपुर डिवीज़न में एक किलोमीटर रेलवे लाइन भी यात्री सुविधा के नाम पर प्रारम्भ नहीं की गई है। जितनी भी रेल लाइन बिछाई गई हैं वे सब की सब मालगाड़ियों की आवश्यकताओं के देखते हुए मजबूरी में बिछाई गई हैं फलस्वरूप बिलासपुर-अंबिकापुर, दुर्ग-जगदलपुर, बिलासपुर-मंडला-जबलपुर, कोरवा-जशपुरनगर-रांची जैसी नई लाइनों की मांग नक्कारखाने में तूती की आवाज़ साबित हुई है। रेलवे भर्ती दफ्तर इस डिवीज़न में नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों की रोज़गार के मामले मे भी उपेक्षा हो रही हैं..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Will you please conclude? we had a debate on the Railway Budget just last week.

SHRI GOVINDRAM MIRI: I am concluding, Sir.

नई यात्री रेल गाड़ियां शुरू नहीं की जाती हैं क्योंकि मालगाड़ियों के अत्यधिक चलने के कारण रेलवे ट्रैक सदैव व्यस्त रहते हैं। यहां तक कि समस्त इस्पात कारखानों तथा राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर, बोकारो से